



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 235]
No. 235]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 1998/चैत्र 23, 1920
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 1998/CHAITRA 23, 1920

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1998

का०आ० 319(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन कॉटन एसोसिएशन, इंदौर द्वारा मान्यता, नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को रुई में अग्रिम संविदा (अपरिवर्तनीय निर्दिष्ट) के बारे में 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2000 (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) तक के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

[मि. सं. 12/(16)/आई. टी/98]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 1998

S.O. 319(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Cotton Association, Indore and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period from 1st April, 1998 to 31st March, 2000 (both days inclusive) in respect of forward contracts (NTSDC) in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/(16)/IT/98]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

